माननीय प्रधानमंत्री के 12 साल बेमिसाल : सेवा, सुशासन, जनकल्याण

व्याख्यानमाला –7

भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत@2047

वक्ता

श्री कवीन्द्र प्रताप सिंह

इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस पूर्व आई0पी0एस अधिकारी

दिनांक 15 जून 2026 पुर्वाहन 11:00 बजे

कार्यक्रम संरक्षक एवं अध्यक्ष

आचार्य सत्यकाम जी

माननीय कुलपति

नोडल अधिकारी कार्यक्रम

प्रोफेसर संजय कुमार सिंह

भूगोल, समाज विज्ञान विद्याशाखा

आयोजक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj
12 साल बेमीसाल
12 UNPARALLELED YEARS
Trust, Development, Public Welfare
5 to 21 June 2026
Congratulations on successfully completing 12 Glorious and Unparalleled Years of Governance!
#12SaalBemisaal #ViksitBharat2047

उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
द्वारा आयोजित
व्याख्यानमाला
20 जून 2026 | अपराह्न 12.00 बजे से
विषय: "भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत @2047"
12 साल बेमीसाल
12 UNPARALLELED YEARS
विश्वास, विकास, जन कल्याण
5 से 21 जून 2026
प्रमुख वक्ता एवं पदाधिकारी
संरक्षक एवं अध्यक्ष
आचार्य सत्यकाम
माननीय कुलपति,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
मुख्य वक्ता
श्री कवीन्द्र प्रताप सिंह
पूर्व आई. पी. एस. (इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस)
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रान्त अध्यक्ष विहिप काशी प्रान्त
कार्यक्रम अधिकारी (नोडल)
प्रो. संजय कुमार सिंह
भूगोल विभाग,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
धन्यवाद ज्ञापन
प्रो. आनंदानंद त्रिपाठी
राजनीति विज्ञान विभाग,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
ज़ूम मीटिंग आई. डी : 999 1423 4939
पासवर्ड: 1234
व्हाट्स ग्रुप लिंक
https://chat.whatsapp.com/Gy6k50nNVjxAlccgnyVms6
संपर्क: 7525048007
#12SaalBemisaal #ViksitBharat2047
संपर्क: 7525048007

उ0प्र0 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

केन्द्र सरकार के 12 वर्ष : सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण

व्याख्यानमाला – 2026

भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत@2047

दिनांक
20 जून 2026
(शनिवार)

समय
दोपहर 12.00
बजे से

माध्यम
ऑनलाइन

संरक्षक एवं अध्यक्ष

आचार्य सत्यकाम
माननीय कुलपति
उ0प्र0राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

मुख्य वक्ता

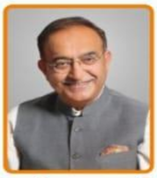

श्री कवीन्द्र प्रताप सिंह
पूर्व आईपीएस (इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस)
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
प्रांत अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद
काशी प्रांत

कार्यक्रम अधिकारी (नोडल)

प्रो0 संजय कुमार सिंह
भूगोल विभाग
उ0प्र0राजर्षि टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

धन्यवाद ज्ञापन

प्रो0 आनन्दानन्द त्रिपाठी
राजनीति विज्ञान विभाग
उ0प्र0राजर्षि टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

संचालन

डॅा0 सुनील कुमार
प्राचीन इतिहास विभाग
उ0प्र0राजर्षि टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय
प्रयागराज

zoom

ZOOM MEETING DETAILS

Meeting ID : 99914234939
Passcode : 1234

सूचना हेतु लिंक

https://chat.whatsapp.com/Gy6k50nNVjxAlccgnyVms6

॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन
मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

7525048007

आप सभी का हार्दिक स्वागत है !

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन है

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12ः वर्ष सेवा, सुशासन, एवं जन कल्याण व्याख्यानमाला में आज सातवें दिन का विषय– भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत@2047 था । आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कवीन्द्र प्रताप सिंह ,भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं । कार्यक्रम का संचालन, स्वागत व अभिनंदन डॉ० सुनील जी द्वारा किया गया ,कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह द्वारा विषय प्रवर्तन व वक्ता परिचय दिया गया। कवीन्द्र प्रताप सिंह जी ने बताया कि भारत में शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित पारदर्शी और उत्तरदाई शासन की ओर अग्रसर हो रहा है । भारत में वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक उत्तरदाई व पारदर्शी बनाना है। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध तरीके से हुआ है औपनिवेशिक समय में आईसीएस (इंडियन सिविल सर्विसेज) व आईपी (इंपीरियल पुलिस) थी अब यह अपने नए स्वरूप में आई ए यस (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज) व आईपीएस (इंडियन पुलिस सर्विस) हो गया है । पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति तथा आर्थिक सुधारो के माध्यम से देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किया है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन आया है । 21वीं सदी में आईटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, और ई गवर्नेंस ने शासन व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था मुख्यतरू नियंत्रण और नियमों के पालन तक सीमित थी परंतु वर्तमान समय में शासन की अवधारणा बदल चुकी है , अब शासन का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं बल्कि नागरिकों की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। समय के साथ प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को महत्व दिया जाने लगा है । 21वीं सदी में तकनीकी विकास नें शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है आज लाइसेंस, प्रमाण पत्र, प्रवेश प्रक्रिया, बैंकिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं । कोविड महामारी के दौरान तकनीक की उपयोगिता और स्पष्ट हो गई है ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने सिद्ध किया की तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुका है । ई –गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है । शिकायत निवारण प्रणाली (आई आर जी एस) के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता न्याय और स्वतंत्रता है केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मापदंड नहीं है मानव विकास, शिक्षा स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा भी विकास के महत्वपूर्ण संकेत हैं वर्तमान समय में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है इसके लिए तकनीक आधारित शासन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। देश में स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को गति दी जा रही है । भारत में शासन व्यवस्था शासन से सुशासन की ओर निरंतर अग्रसर है तकनीक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय तथा समावेशिता इसके प्रमुख आधार हैं। विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसके लाभ को पहुंचना है । कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन माननीय कुलगुरु आचार्य सत्यकाम जी ने किया , कुलगुरु ने कहा कि शासन का अर्थ रूल करना नहीं बल्कि सेवा भाव है और यह भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। शासन का जनता के पास पहुंचना ही सुशासन है। ई गवर्नेंस ने शासन में पारदर्शिता लाई है कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आनंदानन्द त्रिपाठी जी द्वारा किया गया प्रो० त्रिपाठी ने कहा मुख्य वक्ता के लिए कहा कि रिटायरमेंट इस नॉट ए फुल स्टाप इट्स अ कामा...

News Letter

मुक्त चिन्तन

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम संख्या 10, 1999 द्वारा स्थापित

मुक्त चिन्तन 20 जून, 2026

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यानमाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयए प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के *'12 वर्ष सेवाए सुशासन एवं जनकल्याण'* कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन **'भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत–2047'** विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति **आचार्य प्रोफेसर सत्यकाम** ने कीए जबकि मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशासनिक विशेषज्ञ **श्री कविन्द्र प्रताप सिंह** उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील जी द्वारा किया गया। विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी **प्रोफेसर संजय सिंह** ने प्रस्तुत किया।

विकसित भारत–2047 के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक - केपी सिंह

व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। आज लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, बैंकिंग, प्रवेश प्रक्रिया सहित अनेक सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुकी है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री सिह ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे प्रशासन तक पहुँचा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, न्याय और स्वतंत्रता है। केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मानदंड नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास भी विकसित राष्ट्र की पहचान हैं।उन्होंने विकसित भारत-2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए तकनीक आधारित शासन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएँ देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं।

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप - प्रोफेसर सत्यकाम

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुँचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहाँ प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। इसके लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीक का सदुपयोग और नैतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय परंपरा में शासन को सदैव जनसेवा का माध्यम माना गया है। ई-गवर्नेंस ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

1:20
63
केंद्र सरकार के 12 वर्ष की ...
REC
RC
Ayodhya
Ayodhya
Satyakam Roy
Unmute
Stop video
30
Chat
58
Participants
More
Leave

12:17
77
RC
Ayodhya
Ayodhya
Kavindra Singh

RC Ayodhya
Ayodhya
Prof. Sanjay Singh

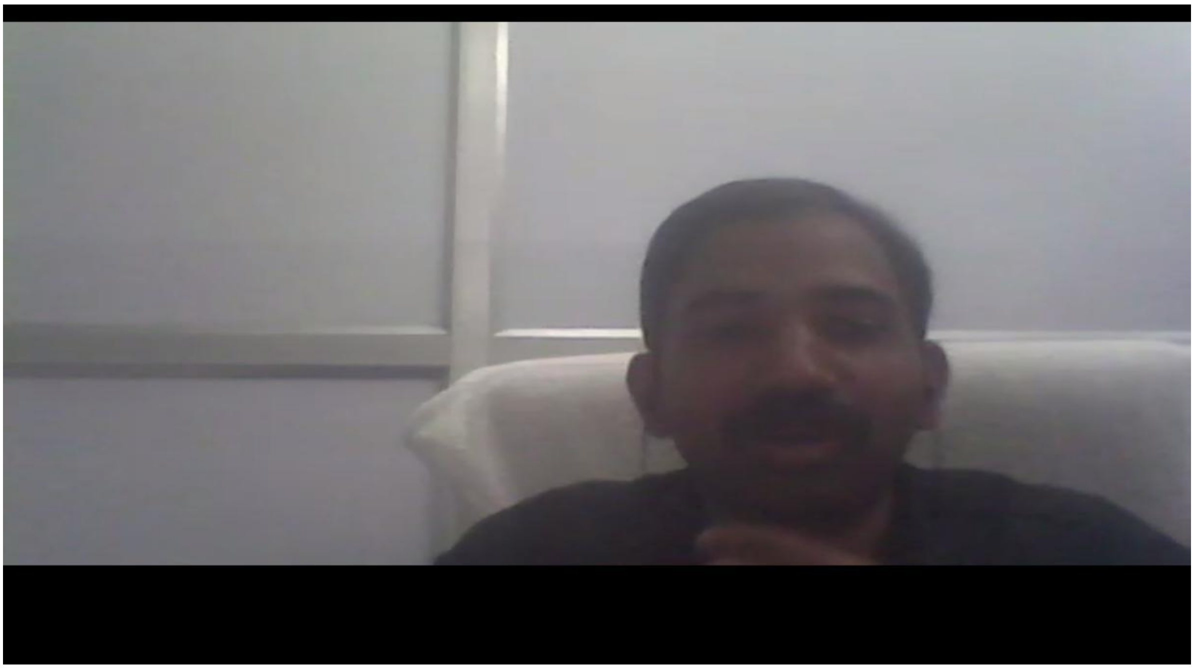

1:27
REC
BABITA SHUKLA
Dr. Digvijay Vishwakarma
Jaunpur
Dr. Sunil Kumar
Dr.Ananda Nand Tripathi
Kavindra Singh
Piyush Datt Mishra,RSC
Geography
RC
Ayodhya
Ayodhya
Participants (57)

1:29
Dr. Sunil Kumar
Dr.Ananda Nand Tripathi
Kavindra Singh
Piyush Datt Mishra,RSC
Geography
Prof. Sanjay Singh
prof.Santosha kumar
1234
28 Shivans
RC
Ayodhya
Ayodhya

12:07
Dr. Digvijay Vishwakarma Jaunpur
Dr. Sunil Kumar
Kavindra Singh
Prof. Sanjay Singh
डॉ दुर्गेश प्रताप सिंह रायबरेली
1234
Abhilash kumar Reseacrh scholar
Amit Patel Scholar Ge
RC Ayodhya Ayodhya

12:24
Dr. Digvijay Vishwakarma Jaunpur
Dr. Sunil Kumar
Dr.Shailendra Kumar singh
Kavindra Singh
Piyush Datt Mishra,RSC Geography
Prof. Sanjay Singh
Prof. Satya Pal Tiwari
1234
RC Ayodhya Ayodhya

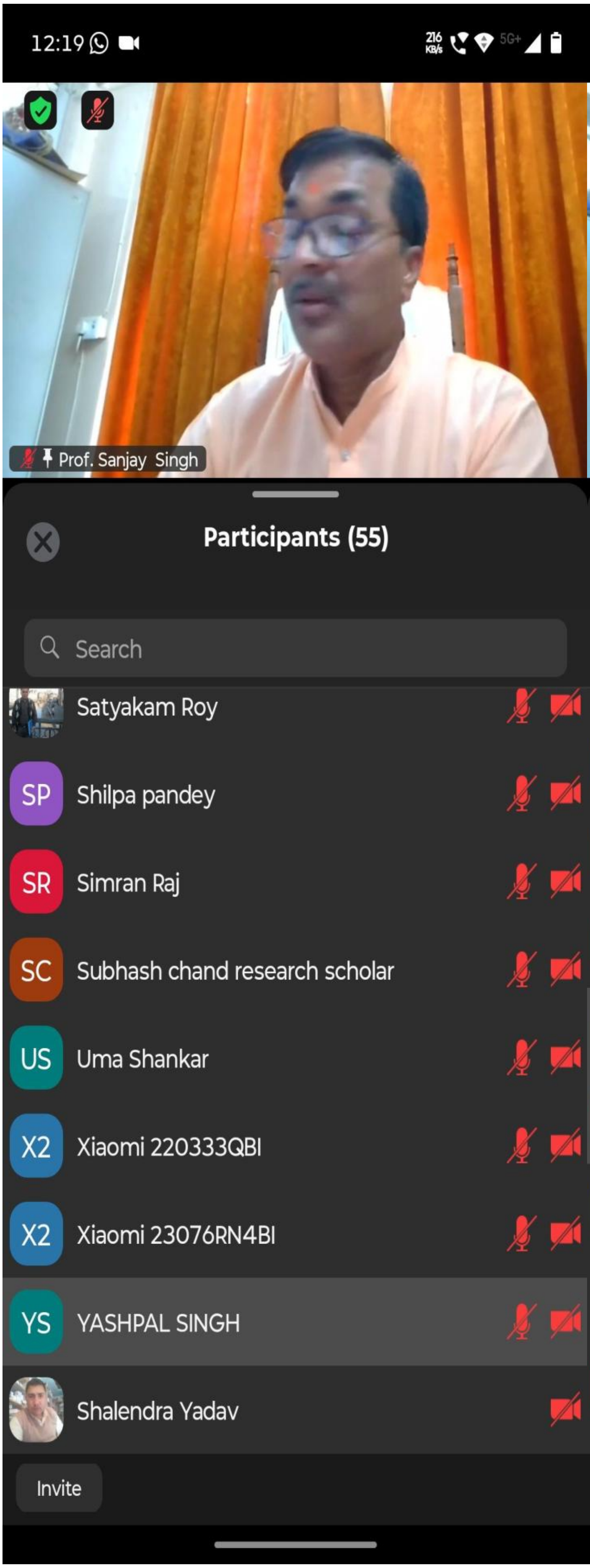
12:19
Prof. Sanjay Singh
Participants (55)
Search
Satyakam Roy
SP Shilpa pandey
SR Simran Raj
SC Subhash chand research scholar
US Uma Shankar
X2 Xiaomi 220333QBI
X2 Xiaomi 23076RN4BI
YS YASHPAL SINGH
Shalendra Yadav
Invite
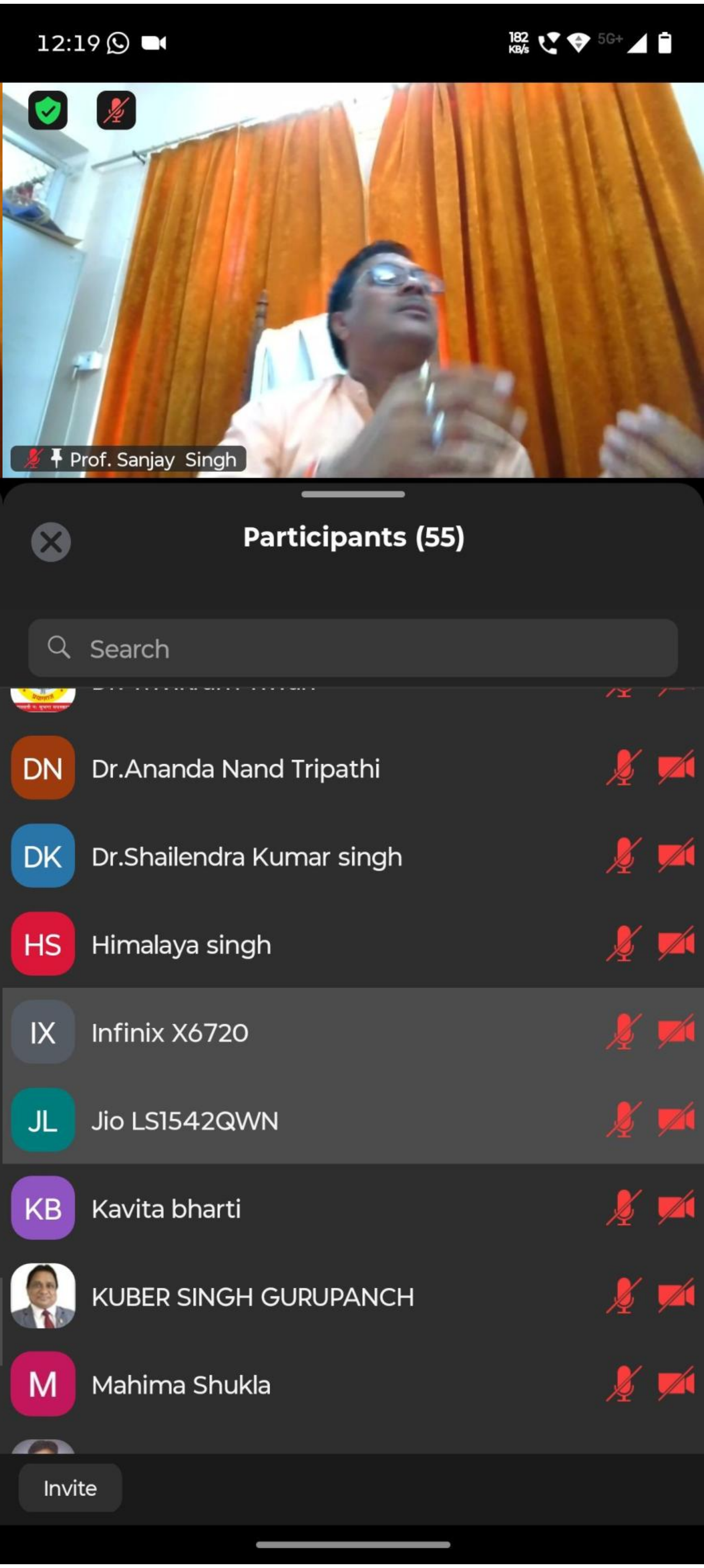
12:19
Prof. Sanjay Singh
Participants (55)
Search
DN Dr.Ananda Nand Tripathi
DK Dr.Shailendra Kumar singh
HS Himalaya singh
IX Infinix X6720
JL Jio LS1542QWN
KB Kavita bharti
KUBER SINGH GURUPANCH
M Mahima Shukla
Invite

भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई – केपी सिंह

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप - प्रोफेसर सत्यकाम

प्रयागराज ।उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत-2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री सिह ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और

नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे प्रशासन तक पहुँचा सकता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है।

जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार ने तथा विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आनन्दानंद त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

परिषद ने इस समस्या को ध्यान में रखते निर्देश दिए हैं। | डेलिगेट, राजनेता, नौकरशाह, हस्तियां, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट आभा त्रिपाठी आदि ने हार्दिक बधाई दी है।

विकसित भारतऽ2047 के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक: केपी सिंह

▶▶ गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप: प्रो सत्यकाम

तिजारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारतऽ2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त आईपीएस कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना

नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुँचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारतऽ2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहाँ प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। इसके लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीक का सदुपयोग और नैतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक हैं। जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार ने तथा विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय व्याख्यान माला के नोडल अधिकारी प्रो संजय सिंह ने प्रस्तुत किया।

Lonavala - Kalyan - Vasai Rd - Surat - strengthens regional connectivity. of Uttar Pradesh, senior human-wildlife conflict in

Transparent and Technology-Enabled Good Governance Essential for Developed India 2047: K.P. Singh

Quality of Life is the True Essence of Good Governance: Professor Satyakam

JE CORRESPONDENT

Prayagraj: As part of a lecture series organized by Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj, commemorating 12 years of service, good governance, and public welfare initiatives of the Central Government, an online lecture on "Indian Good Governance and Developed India–2047" was held on Saturday, the seventh day of the series.

The Chief Guest and keynote speaker, former senior Indian Police Service (IPS) officer Kavindra Pratap Singh, stated that India's governance system has continuously evolved over time. Moving beyond traditional administrative structures, the country is now progressing toward a technology-driven, transparent, and accountable governance framework. He said that the objective of good governance today is not merely to administer but to provide quality services to citizens, ensure inclusive development, and make administration more accountable and transparent.

He noted that the Indian administrative system has developed in phases. The administrative and policing structures of the colonial era, such as the ICS and IP systems, have evolved into the modern Indian Administrative Service (IAS) and Indian Police Service (IPS). Significant transformations in India's economy and governance mechanisms followed the Five-Year Plans, the Green Revolution, economic reforms, and the economic liberalization of 1991.

Mr. Singh emphasized that information technology has provided a new direction to governance in the 21st century. The Right to Information Act, e-governance, digital services, and online platforms have made administration more citizen-centric. Today, numerous government services, including licenses, certificates, banking, and admission processes, are available online. The COVID-19 pandemic demonstrated that technology has become an integral part of modern governance through online education, digital payments, video conferencing, and the digitization of various government services.

The former IPS officer further stated that e-governance has strengthened communication between the government and citizens. Through grievance redressal systems, ordinary citizens can directly convey their concerns to the administration. He remarked that equality, justice, and liberty form the foundation of Indian democracy. Economic progress alone is not the benchmark of development; education, healthcare, social security, and human development are equally important indicators of a developed nation.

Referring to the vision of Developed India–2047, he said that special emphasis is being placed on technology-driven governance, innovation, the digital economy, quality education, and human resource development. Startup culture, Digital India, Make in India, and various welfare schemes are accelerating the country's economic and social progress.

Presiding over the program, the Vice-Chancellor of the Open University, Professor Satyakam, said that in Indian thought, governance is not merely about exercising power but about public welfare and service. He emphasized that a quality life represents the true essence of good governance. The concept of good governance becomes meaningful only when the benefits of government schemes reach the last person in society with dignity.

He stated that the vision of Developed India–2047 is not merely an aspiration for economic prosperity but for building a nation where every citizen has access to quality education, healthcare, employment, security, and a dignified life. Transparency, accountability, ethical leadership, and the effective use of technology are essential for achieving this goal.

Professor Satyakam further observed that Indian tradition has always regarded governance as a medium of public service. E-governance has made administration more transparent, accessible, and accountable. He called upon the youth to actively participate in nation-building, emphasizing that innovation, social responsibility, and commitment to national interest will play a crucial role in realizing the vision of a developed India.

University Public Relations Officer Dr. Prabhat Chandra Mishra informed that the program was conducted by Dr. Sunil Kumar, who also welcomed and felicitated the guests. The thematic introduction and introduction of the keynote speaker were presented by Professor Sanjay Singh, the Nodal Officer of the lecture series. The vote of thanks was delivered by Professor Anand Anand Tripathi.

Teachers, officers, employees, and a large number of students participated in the program. Dr. Mishra noted that the week-long lecture series proved highly beneficial, enabling the public to gain awareness about the Central Government's significant initiatives and welfare schemes.

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप – प्रोफेसर सत्यकाम

प्रयागराज।। प्रयाग प्रभात न्यूज

प्रयागराज 20 जून उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत दृ2047 विषय पर ऑनलाइन

व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए देश तकनीक आधारित,पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी. एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा वर्ष 1991 के आर्थिक उदारी करण के बाद भारतीय अर्थ व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई–गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। आज लाइसेंस, प्रमाण–पत्र, बैंकिंग, प्रवेश प्रक्रिया सहित अनेक सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुकी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि ई–गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीध े प्रशासन तक पहुँचा सकता है।

development, infrastructure, en- value chains have made Uttar He added that this integration of of various departments, includ- and other welfare schemes. accounts. Hupari-Talgud at the hands of were present.

Transparent and tech-enabled good governance essential for developed India-2047: KP Singh

Quality life true form of good governance: Prof Satyakam

SANYAM BHARAT CORRESPONDENT

Prayagraj: On Saturday, the seventh day of the lecture series organized by Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj under the series of 12 years of service, good governance and public welfare programs of the Central Government, an online lecture was organized on the topic of Indian Good Governance and Developed India-2047.

Chief guest and keynote speaker of the lecture series, Kavinder Pratap Singh, a former senior Indian Police Service officer, said that India's governance system has continuously evolved over time. Moving beyond the traditional administrative structure, the country is now moving towards a technology-based, transparent, and accountable governance system. He said that the objective of good governance today is not just governance, but also providing quality services to citizens, making development inclusive, and making administration more accountable and transparent.

He stated that the Indian administrative system has evolved in stages. The colonial-era ICS and IP systems have evolved into the modern Indian Administrative Service and Indian Police Service. The Five-Year Plans, the Green Revolution, economic reforms, and the 1991 economic liberalization have seen profound changes in the Indian economy and administrative system. Singh stated that information technology has given a new direction to governance in the twenty-first century. The Right to Information Act, e-governance, digital services, and online platforms have made administration people-oriented. Today, many government services, including licenses, certificates, banking, and admission processes, are available online. During the COVID-19 pandemic, online education, digital payments, video conferencing, and the digitization of various government services have proven that technology has become an integral part of modern governance.

Singh, a former IPS officer, said that e-governance has made communication between the government and citizens more effective. Through grievance redressal systems, ordinary citizens can directly communicate their problems to the administration. The fundamental foundations of Indian democracy are equality, justice, and freedom. Economic progress is not the only criterion for development; education, health, social security, and human development are also hallmarks of a developed nation. Referring to the vision of a developed India by 2047, he said that special emphasis is being placed on technology-based governance, innovation, the digital economy, quality education, and human resource development. Startup culture, Digital India, Make in India, and various public welfare schemes are providing new impetus to the country's economic and social development.

Presiding over the program, Professor Satyakam, Vice Chancellor of the Open University, said that in Indian philosophy, governance does not merely mean the exercise of power, but rather the spirit of public welfare and service. He said that a quality life is true good governance. The concept of good governance becomes meaningful only when the benefits of government schemes reach the last person in society with dignity. He said that the dream of a developed India - 2047 - is not merely the goal of economic prosperity, but the creation of a nation where every citizen has access to quality education, health, employment, security, and a dignified life. For this, transparency, accountability, proper use of technology, and ethical leadership are essential.

Professor Satyakam said that in Indian tradition, governance has always been considered a means of public service. E-governance has made administration more transparent, accessible, and accountable. He appealed to the youth, saying that their active participation, innovation, social responsibility, and commitment to national interest will be crucial in building a developed India.

Public Relations Officer Dr. Prabhat Chandra Mishra said that Dr. Sunil Kumar conducted the program, welcomed and felicitated the guests, and the topic was introduced and the keynote speaker was introduced by the nodal officer of the lecture series, Professor Sanjay Singh. At the end of the program, Professor Anandanand Tripathi presented the vote of thanks. University teachers, officers, employees, and a large number of students were present at the program. Dr. Mishra said that this week-long lecture series proved very beneficial, helping the public gain knowledge about the important works and schemes of the Central Government.

---

governance, and public welfare initiatives of the Central Government, an online lecture on "Indian Good Governance and Developed India–2047" was held on Saturday, the seventh day of the series.

The Chief Guest and keynote speaker, former senior Indian Police Service (IPS) officer Kavindra Pratap Singh, stated that India's governance system has continuously evolved over time. Moving beyond traditional administrative structures, the country is now progressing toward a technology-driven, transparent, and accountable governance framework. He said that the objective of good governance today is not merely to administer but to provide quality services to citizens, ensure inclusive development, and make administration more accountable and transparent.

He noted that the Indian administrative system has developed in phases. The administrative and policing structures of the colonial in India's economy and governance mechanisms followed the Five-Year Plans, the Green Revolution, economic reforms, and the economic liberalization of 1991.

Mr. Singh emphasized that information technology has provided a new direction to governance in the 21st century. The Right to Information Act, e-governance, digital services, and online platforms have made administration more citizen-centric. Today, numerous government services, including licenses, certificates, banking, and admission processes, are available online. The COVID-19 pandemic demonstrated that technology has become an integral part of modern governance through online education, digital payments, video conferencing, and the digitization of various government services.

The former IPS officer citizens can directly convey their concerns to the administration. He remarked that

equality, justice, and liberty form the foundation of Indian democracy. Economic progress alone is not the benchmark of development; education, healthcare, social security, and human development are equally important indicators of a developed nation.

Referring to the vision of Developed India–2047, he said that special emphasis is being placed on technology-driven governance, innovation, the digital economy, quality educa- social progress.

Presiding over the program, the Vice-Chancellor of the Open University, Professor Satyakam, said that in Indian thought, governance is not merely about exercising power but about public welfare and service. He emphasized that a quality life represents the true essence of good governance. The concept of good governance becomes meaningful only when the benefits of government schemes reach the last person in society with dignity.

He stated that the vision of Developed India–2047 is not merely an aspiration for economic prosperity but for building a nation where every citizen has access to quality education, healthcare, employment, security, and a dignified life. Transparency, accountability, ethical leadership, and the effective use of technology are essential for achieving this goal.

Professor Satyakam further observed that Indian tradition has always re- the youth to actively participate in nation-building, emphasizing that innovation, social responsibility, and commitment to national interest will play a crucial role in realizing the vision of a developed India.

University Public Relations Officer Dr. Prabhat Chandra Mishra informed that the program was conducted by Dr. Sunil Kumar, who also welcomed and felicitated the guests. The thematic introduction and introduction of the keynote speaker were presented by Professor Sanjay Singh, the Nodal Officer of the lecture series. The vote of thanks was delivered by Professor Anand Anand Tripathi.

Teachers, officers, employees, and a large number of students participated in the program. Dr. Mishra noted that the week-long lecture series proved highly beneficial, enabling the public to gain awareness about the Central Government's significant initiatives and welfare schemes.

विकसित भारत-2047 के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक : केपी सिंह

आनंदी मेल ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत–2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई–गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है।

पारदर्शी सुशासन से ही बनेगा विकसित भारत : केपी सिंह

युनाइटेड भारत

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत शनिवार को 'भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत-2047' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पूर्व आईपीएस अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम शासन व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ने समय के साथ उल्लेखनीय विकास किया है। सूचना का अधिकार, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी बनाया है। कोविड-19 काल में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने तकनीक की उपयोगिता को प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र की पहचान केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा

और मानव विकास से भी होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि भारतीय परंपरा में शासन का उद्देश्य केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और जनसेवा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन का स्वरूप है। जब शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुंचता है, तभी सुशासन सार्थक होता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुनील कुमार ने किया। विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय प्रो. संजय सिंह ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. आनंदानंद त्रिपाठी ने किया। व्याख्यानमाला में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

विकसित भारत-2047 के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक - केपी सिंह

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप - प्रोफेसर सत्यकाम

संयम भारत संवाददाता

प्रयागराज, 20 जून/उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारतङ्ग2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय

योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। आज लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, बैंकिंग, प्रवेश प्रक्रिया सहित अनेक सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुकी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी सिह ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएँ सीधे प्रशासन तक पहुँचा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, न्याय और स्वतंत्रता है। केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मानदंड नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास भी विकसित राष्ट्र की पहचान हैं।उन्होंने विकसित भारतङ्ग2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए तकनीक आधारित शासन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएँ देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुँचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारतङ्ग2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहाँ प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। इसके लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीक का सदुपयोग और नैतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक हैं। प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय परंपरा में शासन को सदैव जनसेवा का माध्यम माना गया है। ई-गवर्नेंस ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार ने तथा विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आनन्दानंद त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। डॉ मिश्र ने बताया कि एक सप्ताह तक चली यह व्याख्यानमाला बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जिससे जनमानस को केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकी।

विकसित भारत-2047 के लिए पारदर्शी एवं तकनीक- सक्षम सुशासन आवश्यक- केपी सिंह

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप- प्रोफेसर सत्यकाम

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के सातवें दिन शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारतङ्ग2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारंपरिक प्रशासनिक ढाँचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध

कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस. और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुँचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारतङ्ग2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहाँ प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो।

जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार ने तथा विषय प्रवर्तन एवं मुख्य वक्ता का परिचय व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आनन्दानंद त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

इलाहाबाद एक्सप्रेस

विकसित भारत के लिए पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम सुशासन आवश्यक : केपी सिंह

गुणवत्तापूर्ण जीवन ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप : प्रो सत्यकाम

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला में शनिवार को भारतीय सुशासन एवं विकसित भारत 2047 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी कविन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पारम्परिक प्रशासनिक ढांचे से आगे बढ़ते हुए आज देश तकनीक आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुशासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना, विकास को समावेशी बनाना तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। औपनिवेशिक काल की आई.सी.एस और आईपी व्यवस्था आज भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के आधुनिक स्वरूप में परिवर्तित हो चुकी है। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, आर्थिक सुधारों तथा 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं।

श्री सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने शासन प्रणाली को नई दिशा प्रदान की है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया है। आज लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, बैंकिंग, प्रवेश प्रक्रिया सहित अनेक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक आधुनिक शासन का अभिन्न अंग बन चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच संवाद अधिक प्रभावी हुआ है। शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार समानता, न्याय और स्वतंत्रता है। केवल आर्थिक प्रगति ही विकास का मानदंड नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास भी विकसित राष्ट्र की पहचान हैं। उन्होंने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके लिए तकनीक आधारित शासन, नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहा कि भारतीय चिंतन में शासन का अर्थ केवल सत्ता संचालन नहीं, बल्कि लोकमंगल और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन ही वास्तविक सुशासन है। जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक पहुंचता है, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का स्वप्न केवल आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण है जहां प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो। इसके लिए पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, तकनीक का सदुपयोग और नैतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। कुलपति ने कहा कि भारतीय परम्परा में शासन को सदैव जनसेवा का माध्यम माना गया है। ई-गवर्नेंस ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

जनसंपर्क अधिकारी डॉ प्रभात चन्द्र मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन, स्वागत एवं अतिथियों का अभिनंदन डॉ. सुनील कुमार तथा विषय प्रवर्तन व्याख्यानमाला के नोडल अधिकारी प्रो संजय सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्रो आनन्दानंद त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। डॉ मिश्र ने बताया कि एक सप्ताह तक चली यह व्याख्यानमाला बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जिससे जनमानस को केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकी।